Samyak
An Institute For Civil Services

MODEL ANSWER 25

Q. Explain the concept of Gross Domestic Product (GDP). Discuss the significance of revising the base year for GDP calculations in India.

Gross Domestic Product (GDP) is a comprehensive measure of a country's economic performance, capturing the monetary value of all final goods and services produced within its borders over a specific period. It is a critical indicator of economic growth or contraction, guiding policy decisions on taxation, public spending, and monetary policy, while also facilitating international comparisons of economic performance.

Gross Domestic Product (GDP) measures a country's economic output using three main approaches: the production approach, which calculates the value added at each stage of production; the income approach, which sums all income earned by individuals and businesses; and the expenditure approach, which aggregates all spending on final goods and services. Moreover, GDP is categorized into nominal GDP, measured at current market prices without adjusting for inflation, and real GDP, which accounts for inflation to reflect true purchasing power.

The base year is a reference year against which GDP for subsequent years is measured. A revision involves recalibrating the base year to reflect the current structure and dynamics of the economy.

Reasons for Revising the Base Year:

- Reflecting Structural Changes: Economic activities evolve with new sectors emerging (e.g., digital economy) and older ones declining.
- Incorporating Updated Data Sets: New data sources and better methodologies improve accuracy.
- Capturing Price Changes: Ensures inflation adjustments align with current price trends.
- International Best Practices: As recommended by the United Nations System of National Accounts (SNA), revisions ensure global comparability.

Significance of the Revision in India:

- Better Policy Formulation: Accurate GDP estimates aid in framing effective economic policies.
- Improved Resource Allocation: Helps identify priority sectors for investment and intervention.
- Economic Indicators Alignment: Synchronizing GDP with other indices like Consumer Price Index (CPI) and Index of Industrial Production (IIP) ensures consistency.
- Enhanced Credibility: Reduces discrepancies and controversies, fostering trust in data.

Although there are several challenges associated with revising the base year for GDP which include methodological concerns, such as replacing traditional datasets like the IIP with MCA-21 data, raising doubts about representativeness. The informal sector, a major contributor to India's economy, often remains underreported. Discrepancies between production and expenditure methods further question accuracy, while economic disruptions like demonetization or COVID-19 complicate the choice of a stable base year.

To address these challenges, adopting a transparent methodology, enhancing data collection for the informal sector, and synchronizing GDP metrics with other economic indicators like CPI and IIP are

Samyak An Institute For Civil Services

essential. Selecting a base year during periods of economic stability and incorporating double deflation methods can ensure robust and credible GDP estimates.

Samyak
An Institute For Civil Services

प्रश्न: सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की अवधारणा को समझाइए। भारत में जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने के महत्व पर चर्चा कीजिए।

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन का एक व्यापक माप है, जो एक विशिष्ट अवधि में अपनी सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। यह आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जो कराधान, सार्वजनिक व्यय और मौद्रिक नीति पर नीतिगत निर्णयों में अहम भूमिका निभाता है। यह साथ ही आर्थिक प्रदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय तुलना की सुविधा भी देता है।

सकल घरेलू उत्पाद तीन मुख्य दृष्टिकोणों का उपयोग करके किसी देश के आर्थिक उत्पादन को मापता है: उत्पादन दृष्टिकोण, जो उत्पादन के प्रत्येक चरण में जोड़े गए मूल्य की गणना करता है; आय दृष्टिकोण, जो व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित सभी आय को जोड़ता है; और व्यय दृष्टिकोण, जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर सभी खर्चों को जोड़ता है। इसके अलावा, जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में वर्गीकृत किया जाता है, जिसे मुद्रास्फीति के लिए समायोजन किए बिना वर्तमान बाजार मूल्यों पर मापा जाता है, और रियल जीडीपी, जो वास्तविक क्रय शक्ति को दर्शाने के लिए मुद्रास्फीति को ध्यान में रखता है।

आधार वर्ष एक संदर्भ वर्ष है जिसके आधार पर बाद के वर्षों के लिए जीडीपी को मापा जाता है। आधार वर्ष में संशोधन अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना और गतिशीलता को दर्शाने में मदद कर सकता है।

आधार वर्ष को संशोधित करने के कारण:

- संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करना: नए क्षेत्रों के उभरने (जैसे, डिजिटल अर्थव्यवस्था) के साथ आर्थिक गतिविधियाँ विकसित होती हैं।
- अपडेट किए गए डेटा सेट को शामिल करना: नए डेटा स्रोत और बेहतर कार्यप्रणाली सटीकता में सुधार लाएगी।
- मूल्य परिवर्तनों को कैप्चर करना: यह सुनिश्चित करता है कि मुद्रास्फीति समायोजन वर्तमान मूल्य प्रवृत्तियों के साथ संरेखित हो।
- अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास: जैसा कि संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए) द्वारा अनुशंसित है, संशोधन वैश्विक तुलनीयता सुनिश्चित करते हैं।

आधार वर्ष में संशोधन का महत्व:

- बेहतर नीति निर्माण: सटीक जीडीपी अनुमान प्रभावी आर्थिक नीतियों को तैयार करने में सहायता करेंगे।
- बेहतर संसाधन आवंटन: निवेश के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद होगी।
- आर्थिक संकेतक संरेखण: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) जैसे अन्य सूचकांकों के साथ जीडीपी को संरेखित करना स्थिरता सुनिश्चित करेगा।
- बढ़ती विश्वसनीयता: विसंगतियों और विवादों को कम करेगा। साथ ही, यह डेटा में विश्वास बढ़ाएगा।

हालांकि जीडीपी के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने से जुड़ी कई चुनौतियाँ भी हैं, जिनमें पद्धतिगत चिंताएँ शामिल हैं, जैसे कि आईआईपी जैसे पारंपरिक डेटासेट को एमसीए-21 डेटा से बदलना, जो प्रतिनिधित्व के बारे में संदेह पैदा करता है। अनौपचारिक क्षेत्र, जो भारत की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता है, अक्सर सही से रिपोर्ट नहीं किया जाता है। उत्पादन और व्यय विधियों के बीच विसंगतियाँ सटीकता पर और भी सवाल उठाती हैं, जबकि विमुद्रीकरण या COVID-19 जैसे आर्थिक व्यवधान एक स्थिर आधार वर्ष के चुनाव को जटिल बनाते हैं।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, एक पारदर्शी पद्धति को अपनाना, अनौपचारिक क्षेत्र के लिए डेटा संग्रह को बेहतर करना और जीडीपी मेट्रिक्स को सीपीआई और आईआईपी जैसे अन्य आर्थिक संकेतकों के साथ समन्वयित करना आवश्यक है। आर्थिक स्थिरता की अवधि के दौरान आधार वर्ष का चयन करना और दोहरी अपस्फीति विधियों को शामिल करना मजबूत और विश्वसनीय जीडीपी अनुमान सुनिश्चित कर सकता है।

Samyak An Institute For Civil Services